

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,
सरिय,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक: 17 जनवरी, 2010.

विषय: अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चालू भवन निर्माण शायों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके संख्या: 5ख1/22992/एस.सी.पी./2009-10,

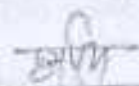
दिनांक: 16 जुलाई 2009, के संबंध में तथा शासनादेश संख्या: 437/XXIV-3/09 दिनांक: 27 दिसम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्या 1610/XXIV-3/07/02(115) 05 टी.सी. दिनांक 17 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) अन्तर्गत निम्नांकित 02 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ -4 पर उल्लिखित पुनरीक्षित लागत पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुये अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ-5 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ-6 पर अंकित विवरणानुसार कुल रु० 77.08 लाख (रुपये सतहत्तर लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में शासनादेश संख्या: 1423/XXIV -3/09/02(34)2009 दिनांक 15 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके नियंत्रण पर रखी गयी धनराशि रु० 250.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्र० सं०	विद्यालय / जनपद का नाम	कुल अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत हेतु संस्तुत धनराशि
1.	02	03	04	05	06
01	स० उ० मा० वि० आली बमोली	70.00	123.54	70.00	53.54
02	स० उ० मा० वि० नेतसोकरी, बमोली	70.00	93.54	70.00	23.54
	कुल योग-	140.00	217.08	140.00	77.08

1. उल्लिखित विद्यालयों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामी/बाड़ी में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने से पूर्व उक्त के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं० 475/XXVII(7)/2008 दि० 15.12.08 के अनुसार



निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं निर्धारित समयसारिणी के अनुसार प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तांतरित करा लिया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। निर्माण इकाई उक्त पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

6. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मदद नजर रखते हुए एवं लोअनि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/बिधिधियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भूतली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसीमद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

11. जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. शासनादेश संख्या: 2047/Xiv-219(2008) दिनांक: 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-30 के अधीन लेखा शीर्षक- 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति

मार्ग

पर पूंजीगत परिणय, 01- सामान्य शिक्षा, 202- माध्यमिक, 00-आयोजनागत-02 अनुसूजा0 के लिए स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान-0201 अनुसूजा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0/इ0 कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण- 24-बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित्त विभाग के असासकीव संख्या 748(P)XXVII(3)09-10 दिनांक 14 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय
/
(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1952(1)/XXIV-3/09/02(115)05 . तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल- पीडी।
7. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल-पीडी।
8. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
9. जिलाधिकारी, चमोली।
9. कोषाधिकारी, चमोली।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली।
11. सम्बन्धित निर्माण एजेंसी
12. वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन
14. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून
15. सम्बन्धित निर्माण एजेंसी
16. मार्ट फाइल।

आज्ञा से

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।